leaves them financially vulnerable. Immediate measures should be taken to clearly define their work and accordingly introduce a separate pay scale and other service benefits.

Investing in the welfare of ASHA workers is an investment in public health and social well-being. Ensuring a fair pay structure will definitely boost the morale of ASHA workers and encourage them to stay in the programme leading to greater continuity and effectiveness of healthcare services. In this context, I urge upon the Central Government to appoint a high-level Commission to study the factual position and to make necessary recommendations for the betterment of ASHA workers.

Demand to declare those people who were in jail during the Emergency in the country as Democracy Fighters and be provided facilities like freedom fighters

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): महोदय, गुजरात के छात्रों ने 1974 में महँगाई को लेकर मुख्य मंत्री के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूँका था। इस आंदोलन का नेतृत्व जय प्रकाश नारायण ने किया। आंदोलन से सरकार गिर गई। 25 जून, 1975 को इमरजेंसी लागू कर सरकार ने जय प्रकाश नारायण को जेल भेज दिया, जिससे देश के तमाम संगठन एक साथ खड़े हुए। हजारों लोग जेल में बंद कर दिए गए। इन सेनानियों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। देश में 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल लगाया गया। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों लोगों को मीसा व डीआईआर के तहत जेल में बंद कर दिया गया था। देश में इमरजेंसी के दौरान जेल में बंद रहे लोगों को लोकतंत्र रक्षक सेनानी/लोकतंत्र सेनानी घोषित किया जाए। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार "सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास" के मूल मंत्र पर काम कर रही है, जिसमें हम लोग अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। लोकतंत्र सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बचाने में पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे योद्धाओं का मान प्रधान मंत्री, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कभी कम नहीं होने देगी।

मैं सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि लोकतंत्र सेनानी परिषद गठित हो और उन्हें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की तर्ज़ पर सम्मान पत्र मिले। इसके साथ ही, लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भाँति सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और पेंशन दी जाए।

Demand for arranging drinking water in Coal mines area

श्री खीरू महतो (बिहार): महोदय, कोल इंडिया ने कोयला खनन क्षेत्र में लाखों एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है और बड़े-बड़े ओपन कास्ट प्रोजेक्ट्स खोले हैं। इन प्रोजेक्ट्स की गहराई 100-200 मीटर है। कुछ में काम चल रहा है, तो कुछ में पानी भरा हुआ है। सैकड़ों गाँव विस्थापित क्षेत्र में पड़ते हैं। वहाँ पेयजल की काफी किल्लत है। इन पानी से भरे कोयला खदानों से गाँवों में

पेयजलापूर्ति की जाए, ताकि भू-विस्थापित परिवारों की पेयजल की समस्या दूर हो सके, क्योंकि खदान चलने के कारण वहाँ पानी का लेवल घट गया है, गाँवों में पानी के कुएँ सूख गए हैं और चापाकलों से पानी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ पत्थर के बड़े-बड़े डम्प्स हैं, जिनमें से कई डम्पों में आग लगी हुई है, जिससे इस क्षेत्र के लोग वायु प्रदूषण से भी त्रस्त रहते हैं। इन डम्पों को गाँवों के बीच पहाड़ जैसा छोड़ा गया है। केन्द्र सरकार पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर पाती है, जिससे यह परेशानी गाँववासियों को होती है।

अतः मैं कोल इंडिया, भारत सरकार से माँग करता हूँ कि जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में नल द्वारा जल दिया जाता है, उसी तरह कोयला खान के बन्द पड़े खदानों से पेयजलापूर्ति भू-विस्थापितों/ग्रामीणों के गाँवों में की जाए। कोयला क्षेत्र में राज्य सरकारें नल द्वारा जल आपूर्ति नहीं करती और यह कहती हैं कि वहाँ जलापूर्ति करने की जवाबदेही कोल इंडिया की है। मैं माननीय कोयला मंत्री, भारत सरकार से इस पर ध्यान देने तथा वहाँ पेयजलापूर्ति करने की माँग करता हूँ।

Concern over failure of Hybrid Bt-cotton (commercialised GM-crop)

SHRI ANEEL PRASAD HEGDE (Bihar): Hybrid Bt. Cotton, which has no trait for yield enhancement, the only commercialized GM crop, has failed conclusively.

The Government submitted in its affidavit in the Delhi High Court that Bt. Cotton seeds are now unaffordable to farmers due to high royalties charged by Mahyco Monsanto Biotech Ltd. which has a near monopoly on Bt. Cotton seeds and that this has led to a market failure.

Contamination by GMOs of non-GMO crops/natural environment is our outstanding concern. India is one of the 17 listed international hotspots of diversity (includes mustard/brinjal/rice). India is the world's centre of brinjal diversity with 2,500+ varieties/wild species. In rapeseed mustard, India has over 9,000+ varieties in our gene bank. With a commercialized GM crop, contamination is certain. The precautionary principle must apply.

There is no coexistence between GMO/Non-GMO farming. Organic farming is India's competitive strength. We are world leaders in organic exports. With contamination, we will lose our non-GMO export markets of thousands of crores. India is the world's largest producer of milk, pulses and millets and the second-largest of rice/wheat/sugarcane/groundnuts and vegetables, all non-GMO. Only India can certify its non-GMO-soy with confidence, because we are not GMO-growing country.

Unequivocal failure of Hybrid Bt. Cotton, highlighted in Government's admission of market failure/concerns over contamination, underscores banning GM crops in order to safeguard biodiversity and our competitive strengths in non-GMO agriculture. I urge the Government to look into it.